Patrika (Indore), 28th December 2016, Page - 18

यूएस में जॉब नकार रहे इंदौरी आईआईटीयंस

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

एच-1 वीजा पर ट्रंप के बयान से पहले ही ठुकराए करोड़ों के पैकेज, देश में रहकर ही दे रहे मेक इन इंडिया को दम

अभिषेक वर्मा
patrika.com

इंदौर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों में गैर-अमरीकंस को नौकरी देने पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अमरीका आकर नौकरी करने वालों को अमरीकंस का हक नहीं छीनने देंगे। ट्रंप ने एच-1 वीजा पर और सख्ती करने के भी संकेत दिए। उनके बयान का ज्यादा असर यूएस जाने वाले इंदौरी स्टूडेंट्स पर नजर नहीं आ रहा क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों को भांपते हुए वे यूएस में जॉब नहीं करना चाहते। करोड़ों के पैकेजे छोड़कर वे मेक इन इंडिया कैंपेन को दम दे रहे हैं।

दुनियाभर से आईटी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों की पसंद इंडियन स्टूडेंट्स रहे हैं। हर साल कंपनियां आईआईटी और आईआईएम सहित टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंचकर कैंपस प्लेसमेंट में करोड़ों के पैकेज ऑफर करती है। सबसे ज्यादा ऑफर यूएस बेस्ड कंपनियों से रहते हैं। अब कैंडिडेट्स दो करोड़ तक का पैकेज छोड़ देश में ही 40-50 लाख के पैकेज पसंद कर रहे हैं। इंदौर के ही आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट्स इस बार यूएस बेस्ड कंपनियों में प्लेसमेंट नकार रहे हैं। ज्यादातर ने डोमेस्टिक कंपनियों में जॉब की जगह एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कदम बढ़ाए है।

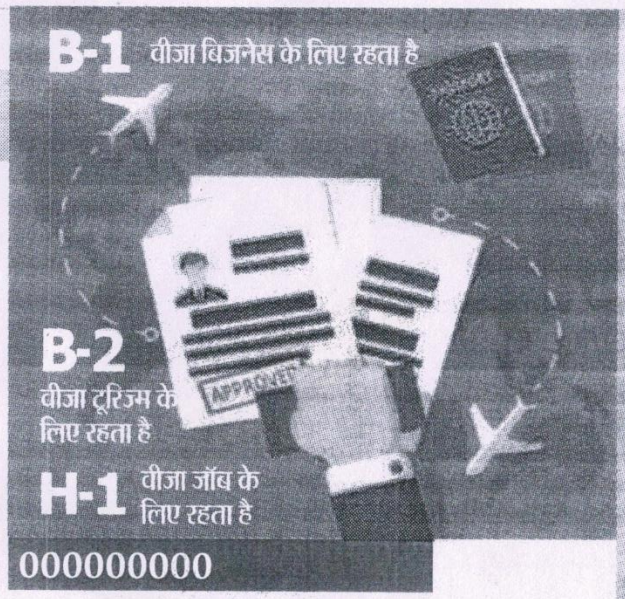

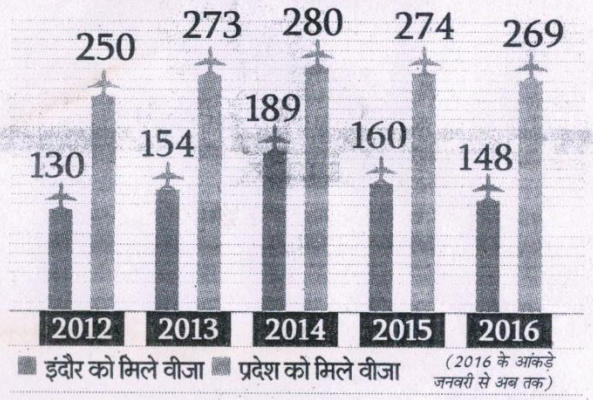

इन्होंने चुना नया रास्ता

आईआईटी इंदौर की 2015 बैच के पासआउट अनमोल अरोरा को यूएस बेस्ड कंपनी से मोटा ऑफर मिला था। अनमोल ने इसकी जगह साथी के साथ स्टार्टअप 'छोटा हॉस्पिटल' शुरू किया। इसमें देश-दुनिया के डॉक्टर और मरीजों को इलाज और इंटरेक्शन का मौका दिया जाएगा। अनमोल का कहना है, 'स्किल के बदले मोटा पैकेज लेकर हम सिर्फ अपना भला कर सकते है। देश में रहकर स्टार्टअप से सोसायटी को भी फायदा पहुंचाना इंपोर्टेंट है।' इसी बैच के ज्वलंत शाह ने स्टार्टअप 'स्वाहा' शुरू किया। ये टाउनशिप्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज में वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा उठा रही है। आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट रोन्सी चावला ने कुछ महीने जॉब की। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस का मौका मिलने पर वे जॉब छोड़कर रिसर्च के लिए चले गए। रोन्सी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया में ही जॉब चाहते हैं।

अभी तक एक वीजा पर तीन दावेदार

आईआईटी और आईआईएम्स से जिन स्टूडेंट्स ने यूएस बेस्ड ऑफिस में प्लेसमेंट को चुना उनमें से कई को जॉइनिंग का मौका ही नहीं मिल पाया है। दरअसल, यूएस में जॉब के लिए एच-1 बी वीजा हासिल करना जरूरी है। यूएस गवर्नमेंट हर साल 65 हजार वीजा जारी करती है, जबकि आईटी कंपनियां ही इससे ज्यादा ऑफर दे देती है। बाकी सेक्टर के ऑफर मिलाकर यूएस जाने को तैयार कैंडिडेट की संख्या 2 लाख तक हो जाती है। ऐसे में कंपनी दूसरे देशों में जॉइनिंग का ऑप्शन देती है। उस देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने से पैकेज भी कम हो जाता है।

अब जॉब देने की बारी

एपल के प्रोडक्ट मैनेजर सिद्धार्थ राजहंस ने बताया, 'ट्रंप की पॉलिसी के कारण इस साल प्लेसमेंट में कई स्टूडेंट यूएस कंपनियों से दूरी बनाए हुए है। प्रोफेशनल्स जॉब ढूंढ़ने के बजाय जॉब देने वाले बनना चाहते है। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर स्कूल लेवल से ही अवेयरनेस आने लगी है। ज्यादातर आईआईटीयन एक्सपीरियंस के लिए कुछ समय जॉब करते है। कैंपस प्लेसमेंट में मिलने वाले करोड़ों के पैकेज वास्तविक नहीं रहते। कंपनियां करीब 20 परसेंट के आरएसयू (रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट) पैकेज में शामिल करती है। इसमें हाउस, कार रेंटल, ट्रैवलिंग अलाउंस के साथ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अलाउंस शामिल रहता है। अभी देखा जाए तो यूएस में डेढ़ करोड़ का पैकेज इंडिया में 25 से 30 लाख रुपए के बराबर है।